मध्य प्रदेश को जनता कपड़े की आपूर्ति

7015. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मध्य प्रदेश को जनता कपड़े की आपूर्ति उसकी मांग की तुलना में अपर्याप्त थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा की गई जनता कपड़े की मांग तथा वास्तव में की गई उसकी आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने मध्य प्रदेश के जरूरत मंद लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले जनता कपड़े की आपूर्ति करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भारत सरकार किसी भी राज्य को जनता कपड़े की आपूर्ति नहीं करती अपितु केवल जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य आवंटित करती है । राज्यों को जनता कपड़े का लक्ष्य आवंटन करना मुख्य रूप से राज्य में हथकरघों की संख्या, उनके द्वारा तैयार किये गये जनता कपड़े की गत प्रगति और देश में जनता कपड़े के कुल लक्ष्य पर निर्भर करता है । सरकार की ऐसी नीति है कि सब्सिडी प्राप्त योजनाओं को धीरे-धीरे समाप्त किया जाये अतः जनता कपड़े को भी धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है ।

(ख) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में गत 3 वर्षों के दौरान आवंटित लक्ष्य, उत्पादन और डिलिवरी का विवरण इस प्रकार है :—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	आवंटित लक्ष्य	उत्पादन	डिलिवरी
1992–93	18.00	15.82	16.68
1993–94	15.00	14.43	12.83
1994–95	13.00	8.79	7.10
		(दिसम्बर, 1994तक)	

(ग) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के कपड़े के उत्पादन की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं :—

1. 10 प्रतिशत से अधिक ग्रे कपड़े का उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए ।

2. प्रत्येक क्षेत्र में तैयार किए जाने वाली मदों की पहचान करके इनका उत्पादन आरंभ करने से पूर्व राज्य स्तर की कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत किया जाये और ऐसी मदों के उत्पादन के लिए विकास आयुक्त हथकरघा से अनुमति ली जाये । इन मदों के आरंभिक मूल्य निर्धारण के लिए भी विकास आयुक्त हथकरघा की अनुमति की आवश्यकता होगी ।

3. उत्पादित किया गया कम से कम 80 प्रतिशत कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसका मूल्य 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर (ऊनी कपड़ों के लिए 34 रुपये प्रति वर्गमीटर) से कम न हो ।

4. कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन रंगे हुये सूत से तैयार समूचे धारीदार/चारखाने डिजाइन/एकरंगा प्रकार का होना चाहिये ।

5. इस योजना के अन्तर्गत मलबरी, टसर, मूंगा सिल्क को छोड़कर सभी फाइबर से तैयार की गई वस्त्र मदों के उत्पादन की अनुमति दी गई है ।

6. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार किया जाने वाला कपड़ा दिये गये नमूने के अनुसार ही होना चाहिये और उत्पादन की प्राप्ति के समय कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिये ।

Fall in cotton prices

7016. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Govt. are aware that stocks of cotton are piling up in Gujarat resulting in glut in the market and consequent fall in prices.

(b) whether it is a fact that Govt. have not only cancelled many of the cotton export quotas which were approved earlier but also resorted to import which forced many market areas in Gujarat to turn down fresh arrivals of cotton in the market;

(c) whether it is also a fact that the Cotton Corporation of India has also stopped buying cotton from market; and

(d) what steps Govt. propose to take to improve this situation to that producers are able to get minimum remunerative prices and squation the demand and supply is maintained?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) In Gujarat, out of an estimated cotton production of about 25 lakh bales, about 20 lakh bales are reported to have already arrived in the current cotton season of 1994-95. Though lately there has been a decline in cotton prices but they are still ruling quite high compared to minimum support price.

(b) Govt. has not cancelled any cotton export quotas. Export of cotton in 1994-95 to the tune of 1.05 lakh bales of Bengla Deshi and Assam Comilla varieties of cotton have been allowed so far, out of 5 lakh bales, in view of domestic demand and prices. Import of cotton was also put under OGL to control the rising prices and augment availability of cotton in the country.

(c) No, Sir.

(d) The minimum support prices fixed by the Govt. are remunerative in nature and since the market prices of cotton are currently prevailing much above support prices, cotton producers are getting remunerative prices.

Dupping of fabrics

7017. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian Cotton Mills Federation has urged Government to take necessary steps to check dumping of fabrics from China, Indonesia and South Korea;

(b) whether fabrics are now being allowed to be imported at an import duty rate of 50 per cent;

(c) whether it is a fact that cost per meter of polyster fabric in China is about 60 per cent lower than that of in India;

(d) whether the costs of inputs in India are higher than those in South Korea, China, Indonesia and Pakistan;

(e) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in Observer dated the 14th April, 1995 under the caption "Industry demands curbs on dumping of fabrics..."; and